

Shri Rajnarain made a number of points about corruption and so on. Sir, there are a series of judgements of the Election Tribunal and the Supreme Court on the question of holding government contracts and licences. Mr. Justice Gokhale need not be reminded about them. He will take care of those decisions. I would like the Minister to bring a comprehensive amendment. I do not know what has happened to the revision of the election law which was going on. I was told it was to be introduced in this Session. Disqualifications are going to be removed. I do not know at what stage the proceedings of this Committee are. I hope that the Government would regard this debate as a provocation for continuing a study of this matter and bring a comprehensive revision of the electoral law.

I would like to make one observation on a very good speech made by Mr. Balachandria Menon who said that there should be age limit also. The Constitution has prescribed an age limit for entering Parliament and the Legislative Assembly. I think Mr. Akbar Khan would agree with me that after 70 nobody should stand for membership. Seventy is a good age for retirement.

SHRI AKBAR ALI KHAN : Agreed.

SHRI A. D. MANI : I make this suggestion to the hon"ble Law Minister. I want to draw the attention of Mr. Justice Gokhale to the suggestion of putting an upper age limit also on candidates standing for election. Politicians should retire at the age of 70. We want young blood to come in. We want this country to be run by new generation

SHRI KRISHAN KANT : What is your age ?

SHRI A. D. MANI : I am 61. Sir, I beg leave of the House, in view of the wishes expressed by Members, to withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 31 GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 16TH NOVEMBER, 1971 REGARDING BENEFIT OF PENSION AND RE-EMPLOYMENT TO EMERGENCY COMMISSIONED OFFICERS

डा० भाई महाध्वर (दिल्ली) : उपसभापति महोदय, पिछली 16 तारीख को मैंने रक्षा मंत्री महोदय से एक सवाल पूछा था, इमरजेन्सी कमीशनड आफिसर्स के बारे में। उस सवाल के संबंध में आधे घंटे की चर्चा करने की आज जो अनुमति मुझे मिली है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, प्रश्न वहाँ से प्रारम्भ होता है जहाँ 1962 में चीनी आक्रमण के समय भारत में संकटकालीन स्थिति घोषित की गई। उस संकटकालीन स्थिति के समय अपने देश के बहुत से जवानों को, बहुत से युवकों को इस बात की प्रेरणा हुई कि देश की रक्षा के लिए, सेना की शक्ति बढ़ाने की इच्छा से वे लौग आए। वे कमीशन लेकर सेना में लड़े, मोर्चों पर गए, उन्होंने तकलीफें उठाई, कुर्बानियाँ भी दीं और 1967 में जब इमरजेन्सी समाप्त हो गई तो उन इमरजेन्सी कमीशनड आफिसर्स को जिनको संक्षिप्त नाम के रूप में ई० सी० ओ० कहा जाता है सेना से मुक्त किया गया और वे लगभग 2 साल के दौरान अलग-अलग टुकड़ों में अलग-अलग वेंचर में मुक्त हुए। उन लोगों ने जिनको कि इस इमरजेन्सी के समय कमीशन दिए गए थे, अनुरोध किया कि सामान्य नियमों में पन्द्रह वर्ष की जो शर्त है पेन्शन के लिए, उसे नरम करके उन्हें भी पेन्शन के उपयुक्त, पेन्शन के योग्य मान लिया जाए। महोदय, काफी देर कोशिश करने के बाद पहली जून, 1969 को यह फैसला लागू किया गया कि जो ई० सी० ओ० उनके बाद रिटायर हुए हैं, यदि वे 15 वर्ष की अपनी सेवा की अवधि पूरी भी नहीं कर चुके थे, लेकिन 12 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके थे तो उनको प्रपोर्शनल पेन्शन, आनुपातिक पेन्शन, दी जाए। यह एक तरह से उस नियम को नरम करने की बात थी, जिन नियम का अगर कठोरता से पालन किया जाता तो ये पेन्शन के लिए हकदार नहीं बनते थे। जहाँ पर मैं सरकार को इस उदारता या इस कंसीड्रेट और न्यायपूर्ण फैसले के लिए बधाई देता हूँ, वहाँ पर मैं यह

[डा. भाई महावीर]

सरकार और इस समय रक्षा मंत्री यहाँ उपस्थित है, उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि इस निर्णय से कुछ लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, वह अन्याय किसी देश को शोभा नहीं देता, क्योंकि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है वह वे ही लोग हैं जिन्होंने संकट के वक़्त अपनी जान जोखिम में डाल कर देश की रक्षा के वास्ते

महोदय, यह प्रश्न इसी में से उठता है कि जिन लोगों को टर्मिनल रीच्युटी दी गई, जहाँ तक मैं जानता हूँ और पुश्ते पता लगा है इसकी जो दर थी वह एक माल की सेवा के लिए 1,000 रु० थी। लगभग तीन, चार साल इमर-जेन्सी के दौरान उन्होंने सेवा की थी। तो औसतन 4,000 रु० के करीब उनको मिला। महोदय, मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो निर्णय किया उसमें, इस थोड़ी सी बचत के कारण, जो उसकी शोभा थी, जो उसके अंदर गुण था, वह गुण बिगड़ा है और वह शोभा नहीं रही। महोदय, कहना यह है कि जिन लोगों को टर्मिनल बेंनिफिट के नाम पर यह कुछ धनराशि दी गई है, वे लोग हैं जिनको पेंशन मिली है। वह किसी रूप में कम नहीं है जो दो वर्षों में बैच में ईसी ब्राज रिलीज किये जाते रहे हैं। तो जो पांच बैच में रिलीज किये जा चुके थे वे कम योग्य नहीं थे। उनका

"According to the rules in force at the time of their release, those Emergency Commissioned Officers who had risen from the ranks and were released before 1st June, 1969, were not eligible for a pension unless they had completed 15 years service. Such of them as did not fulfil this condition were given a terminal gratuity in accordance with their entitlement under the rules."

हक कम नहीं बनता था, जो एक जून के बाद रिलीज होने वाले थे। यह कौन सी रेखा लगाई गई है और इस तरह से लक्षमण रेखा लगाने का क्या कारण है कि इनसे पहले जो जा चुके थे उनको इस पेंशन का हकदार नहीं माना गया, हालांकि दूसरी तरफ जिनको पेंशन मिली है मैं समझता हूँ 100, 115, 150 पेंशन के लिए हकदार बनते हैं—और अगर औसत उम्र गिनी जाय तो 30—32 साल होगी और उन्हें पांच, सात और दस गुना लाभ हो सकता था। और वे उस लाभ के हकदार थे। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को हटाया गया है, जो फिजीकली या मेडिकली अनफिट नहीं थे, प्रारोक्त दृष्टि से जो हट तरह से सक्षम थे, उन्हें रेगुलर कमीशन में नहीं लिया गया और कारण यह था कि रेगुलर कमीशन में स्थान सीमित थे जो किसी और को दिये जा सकते थे। स्थान सीमित होना यह उनका दोष नहीं था। अगर इन कम स्थानों में नहीं आ सके तो इसके कारण दो प्रकार के वर्ग बने उन्ही लोगों में और मैं समझता हूँ कि यह एक अन्याय-पूर्ण बात है और किसी भी सिद्धान्त तथा दृष्टि से उचित नहीं है।

कुछ इसमें और अन्याय की बात मुझे नजर आई और मैं उसे मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता कि जहाँ पर थल सेना या जल सेना के लोग भी जो इमरजेन्सी कमीशन के लिए आये थे उनको इमरजेन्सी समाप्त होने के बाद पुराने पदों पर ले लिया गया। वायुसेना के रैंक में से जो निचले दर्जे के जो कमिश्नर आफ़िसर बन कर आये थे उनको वायु सेना ने वापस नहीं लिया। वायु सेना ने उनसे यह कहा कि जब आप थल सेना में गये तो आपकी जिम्मेदारी थल सेना की हो गई आपको वे ही आवजर्व करें और हम तुमको पुराने स्थानों पर नहीं ले सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि ये लोग न पुरानी नौकरियों में ही लिये गये और न ही इनको पेंशन दी गई और इस तरह से सड़कों पर घूमने के लिए इन्हें छोड़ दिया गया। मैं इनमें से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी सेहत, जिनका स्वास्थ्य, जिनकी मन स्थिति देख कर जिनकी भावना देखकर कोई भी देश गर्व कर सकता है, अभिमान कर सकता है कि वे किस तरह के जबान हैं और किस तरह के उनके विचार हैं। आज हम उनको जगह-जगह पर टोकर खाते देखते हैं अपनी गुजर के लिए और अपनी बीबी बच्चों के निर्वाह के लिए।

महोदय, यह जो विभेद हुआ है, उसको मैं विशेष रूप से सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। यह जो डिसक्रिमिनेशन हुआ, उस विभेद में ई सी ओज की उसी श्रेणी में दो तरह के लोग बन गये हैं जो एक जून, 1969 के पहले रिलीज हो चुके थे और जो एक जून, 1969 के बाद रिलीज हुए। यानी 14 वर्ष 11 महीने और 29 दिन की जो सेवा कर चुके थे, लेकिन वे रिलीज हुए 1 जून के पहले और उनको पेंशन का हकदार नहीं माना गया और जो 1 जून के बाद रिलीज हुए उतनी सेवा में या 12 वर्ष के बाद, उनको पेंशन का हकदार माना गया। इस तरह का जो भेदभाव किया गया है, वह कहाँ तक उचित है? मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर इस दृष्टि से देखे।

मुझे बतलाया गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जिस दिन इस सम्बन्ध में फैसला किया उस दिन के बाद से लागू होता है। रिट्रोस्पेक्टिव एफक्ट, इस तरह के निर्णय को नहीं लिया जा सकता है। हो सकता है फाइनेंस नियमों में और ब्राडिटर के अन्वेषण के नियमों को ध्यान में रख कर सरकार को इस तरह की शर्त लगानी पड़ती है, लेकिन केवल फाइल का चक्कर नहीं है, केवल नियमों की बागीकियों के अन्दर झाड़ लेने का मवाल नहीं है, बल्कि सरकार को सोचना चाहिये कि इस तरह के विषय पर एक मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिये। सरकार को खाम कर उन लोगों का विचार करना चाहिये जिन व्यक्तियों ने देश की पुकार पर अपनी जान हथेली पर रख कर आगे बढ़ने का फैसला किया था। आज इस तरह से एक दिन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फैसला किया उस दिन को हम लोग दिन मान लें और उसके पहिले के लोगों के लिए एक व्यवहार करें और उसके बाद के लोगों के लिए दूसरा व्यवहार करें यह किसी भी दृष्टि से मुझे उचित मालूम नहीं देता है।

मुझे विदित हुआ है और मैं जानता हूँ कि रक्षा मंत्रालय इस हक में शायद है, लेकिन वित्त मंत्रालय इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं सरकार के सामने यह अनुरोध करूँगा कि इस तरह की बात को और इस पक्षपात को अपने पास से दूर करें और इन पुराने ई सी ओज के साथ न्याय करने का फैसला करें।

इसी तरह के पक्षपात और विभेद का एक उदाहरण मेरे सामने और आया है। 1962 के पहले नागा विद्रोहियों के साथ लड़ते हुए जो वीर गति को प्राप्त

हुए थे, जो सेना में जवान आफिसर थे। उनको जो पेंशन मिलती है वह कम है। 20-10-62 को जब यह आपरेशन एरिया डिप्लेयर किया गया था चीनी आक्रमण के समय, उसके बाद जो लोग वहाँ पर काम आये उनको जो पेंशन मिलती है वह ज्यादा है। मैं उन आर्मी आफिसर और जवानों की बात कर रहा हूँ, जो चीन के साथ नहीं बल्कि विद्रोही नागाओं के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। 20-10-62 में चीनी आक्रमण के बाद देश में संकट की स्थिति की घोषणा की गई थी, तो कानूनी तौर पर यह ठीक होगा कि आपरेशन एरिया बनने के बाद पेंशन रुक कुछ ज्यादा हो और उसके पहिले वह कंसेशनल एरिया था जो बाद में नागालैंड बना। कंसेशनल एरिया में जो पेंशन रुक था वे कम थे। तो मेरा आग्रह यह है कि इसमें एक ही श्रेणी के अन्दर आने वाले दो प्रकार के लोगों को केवल इस वास्ते कि उस समय चीन का आक्रमण नहीं हुआ था और उन्होंने जो काम किया वह एक ही तरह का था और उनके साथ भी सरकार को एक ही तरह का व्यवहार करना चाहिए था।

महोदय, मुझे जो कहना था उसको मैं केवल एक बात से समाप्त करूँगा। इस समय राष्ट्रीय संकट है और आज इस प्रश्न को जब मैं उठा रहा हूँ तो मुझको लगता है कि सरकार और इस सदन के सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब देश के ऊपर फिर संकट के बादल हैं, फिर शत्रु हमें ललकार रहा है, हम चाहे कि हमारे जवान जब इस समय देश की रक्षा के लिए भारत की पुकार सुन कर आगे बढ़ें तो ऐसे मौके पर अपने देश के किन्हीं अफसरों या जवानों के मन में यह भावना न रहे कि यह देश या यह सदन या यह सरकार उनकी किसी शिकायत को सुनने में देर लगाती है या सुनने के लिए तैयार नहीं होती। देश के अन्दर विस्फोटक गतिविधियाँ होती हैं। मैं तो यह मान कर चलने के लिए तैयार हूँ कि कई समस्याएँ राजनीतिक दल पैदा करते हैं। अभी कल आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि बिहार प्रदेश के एक मंत्री और एक भूतपूर्व मंत्री के ऊपर सी०वी०आई० ने इस तरह का आरोप सच पाया कि वे पाकिस्तानी तोड़फोड़ करने वालों के साथ मिले हैं। महोदय, ये समस्याएँ ऐसी हैं कि जिन्हें देख कर सेना के कार्य की गम्भीरता, उसकी महत्ता, उसका गौरव और बढ़ जाता है और इसलिए मैं मंत्री महोदय से, सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस बात को केवल राजनीतिक दृष्टि से न देखें। मैंने इसको किसी राजनीतिक लाभ के विचार से नहीं उठाया

[डा० भाई महावीर]

सेना के जवानों के प्रति न्याय हो, पुराने जो कमीशनड आफिसर्स हैं, उनके साथ उदारता का व्यवहार किया जाय, विभेद या पक्षपात जहाँ दिखाया जाता है चाहे वह किसी व्यक्ति के खिलाफ, होने की वजह से न हो, लेकिन फैसलों के चलने में जो देर लगती है उसके कारण एक दिन फैसला हुआ तो उस दिन को पकड़ कर उससे पहले जो चले गए उनके लिए एक अलग दृष्टिकोण यह हमारे लिए शोभा देने वाला चीज नहीं है। इसलिए मैं सरकार से, मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में विचार करके मानवतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं और इस विभेद और पक्षपात की बात को समाप्त करें ताकि सेना के जवानों को यह लगे कि जब हम अपना खून देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सारा देश सहानुभूति में उनके साथ रहता है और उनकी उचित मांगों के वास्ते खड़ा होता है और सरकार भी उनकी बात को उतने ही ध्यान से सुनती है, जितने ध्यान से सुनना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मुझे इस बाद की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य, डा० महावीर ने इस प्रश्न को इस सदन में उठाया। मैं जानता हूँ कि इसमें उनका कोई राजनीतिक विचार नहीं है और न ही सरकार ने इसको राजनीतिक प्रश्न के रूप में अभी तक देखा है। यह प्रश्न तो शुद्ध रूप से शासकीय प्रश्न है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा, इस प्रश्न के ऊपर जो निर्णय होगा, उसका असर केवल इसी प्रश्न तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने और भी उदाहरण दिए, जैसे विद्रोही नागाओं के साथ लड़ने वालों का या उसके बाद के लोगों का जो प्रश्न है। और भी कई तरह के सम्बन्धित प्रश्न हैं। तो अगर एक प्रश्न के ऊपर निर्णय किया जाता है—उसके औचित्य या अनौचित्य का सवाल न भी करें—उसका व्यापक प्रभाव काफी बड़ी मात्रा में हमारे देश में पड़ेगा। यह तो केवल एक सुरक्षा मंत्रालय की बात थी। सुरक्षा मंत्रालय के बाद जो दूसरे और बड़े-बड़े मंत्रालय हैं भारत सरकार के उनमें भी कई ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें एक विशेष तिथि से कोई निर्णय लागू कर दिया गया हो और वैसा करने में अगर कहीं विभेद रहता है तो वह स्वाभाविक है। पहले के एक निर्णय को बदल कर दूसरा निर्णय करते हैं, चाहे उसको ज्यादा उदार बना दें या अनुदार बना दें तो दो विभेद तो हो ही जाते हैं और दो विभेद होने के बाद हम कहें कि उस पर

फिर विचार करना चाहिए तो उनके जो परिणाम होंगे वे इतने दूरगामी होंगे कि उसमें फिर यह नहीं कहा जा सकता कि केवल यह सुरक्षा के जो अधिकारी हैं उन्हीं तक सीमित रहेगा। सुरक्षा दल में काम करने वाले या सेना में काम करने वाले जो लोग हैं वे विशिष्ट महत्व रखते हैं, पर फिर भी मानवीय ढंग से जिस तरह माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को हल करने की बात कही है, मानवीय ढंग हर मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए लागू करना पड़ेगा, हम नहीं कह सकते कि इसको हम सीमित रखें अपनी सेना के लिए और उसके अतिरिक्त दूसरे जो लोग हैं चाहे वे आइनेन्स फ़ैक्ट्री में काम करते हों चाहे बड़े संस्थानों में काम करते हों जहाँ पर भी हैं वहाँ अच्छा काम करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं उनके लिए लागू नहीं होगा। इनलिये जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उसमें काफी बल होते हुये भी मैं उनसे कहूँगा कि जो उसके व्यापक असर होंगे, उम असर की तरफ भी वे ध्यान रखें। जब शासन को ऐसी बातों पर निर्णय करना होता है तो हर एक पक्ष के ऊपर ध्यान देना होता है। मानवीय पक्ष के ऊपर, शासकीय पक्ष के ऊपर, वित्तीय पक्ष हो तो उसके ऊपर और इस तरह जितने भी सम्बन्धित पक्ष हैं सब की तरफ देख कर उसको निर्णय करना होता है कि राष्ट्रहित में सबसे उचित और संतुलित निर्णय क्या हो सकता है। यदि इसको केवल एक सीमित दृष्टि से देखा जाय तो हो सकता है कि हम यह कहें कि सेनाओं के जो असर थे उनके लिये जो यह किया गया इसमें दो तरह का विभेद किया गया और यह कोई अच्छी चीज नहीं दिखती है। सीमित दृष्टि से देखा जाय तो मैं समझता हूँ कि यह चीज उचित नहीं दिखती पर यदि इसको व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से इस विभेद को हम समाप्त कर सकते हैं। काफी सहानुभूतिपूर्वक, काफी गम्भीरता से और गहराई से इस पूरे प्रश्न पर विचार किया गया और उसके बाद ही यह निर्णय किया गया कि अभी जिस प्रकार का हमने निर्णय लिया 1969 में उस निर्णय को यदि हम उसके पहले भी लागू करें तो फिर इतनी लम्बी-लम्बी चीजें और इतने दूसरे तरह के व्यापक प्रश्न इसमें से आ जायेंगे जिनके लिये नहीं करना संभव नहीं होगा और एक ऐसी स्थिति तैयार होगी जिसमें किसी के लिये भी नहीं करना संभव नहीं होगा। जो वित्तीय नियम बने हुये हैं, उनके अनुसार भी असाधारण परिस्थिति में निर्णय करने के लिये जो गाइड लाइन्स बनी हुई

है, उनके इतना मत है कि इसमें कल्पना का दावा श्रेयस्कर वा । यह बात हर दो बात का सरकार ने निर्णय किया कि जिन व्यक्तियों को जून, 1969 के पहले इमरजेंसी कमीशन ने प्रत्यक्ष किया गया था जो प्रत्यक्ष रूप से उनका इस तरह की मुक्तिदान देने में वेसी प्रशासन-कीय, विचार्य और तरह-तरह की कठिनाइयां उत्पन्न होगी जिनसे कुछ लोगों को फायदा प्रत्यक्ष होना पर बहुतों को उन्हें काफी कठिनाई हो सकती है और अन्याय में जो आवेद यह बात पूर्ण तरह में न जमे । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इस बात पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिये, बल्कि माननीय सदस्य ने इस बात को ध्यान पर उठाया है इसलिए हम लोग इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने और यह देखने का फल करेंगे कि किसी तरह से कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं । मैं यह नहीं कह सकता कि कोई रास्ता निकलना या नहीं निकलना । पर यह बात प्रत्यक्ष है कि हम लोग माननीय पक्ष में, न्यायोचित पक्ष में इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि जिन तरह में हम इसका हल निकाल सकें । पर यदि कोई हल न निकल सका और यदि हम आज की स्थिति में कोई फेरबदल न कर सकें तो माननीय सदस्य इस बात का कदापि यह मतलब न निकालें कि हम लोग इस बात का महत्व नहीं समझते । या इस बात को उचित नहीं मानते हैं । पर वास्तव रूप में देख कर हम इस बात को समझते हैं कि इसमें व्यापक शिवां को रक्षा नहीं हो सकती । जो फिर हो सकता है कि यह निर्णय को हम न बदलें । फिर भी हम लोग किसी तरह में बन्द दिमाग में इस प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे, हम खुले रूप से इस बात के ऊपर विचार करने और इस बात की सोचेंगे कि किस रूप में हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं । मैं कोई किसी तरह का आवासन नहीं दे रहा हूँ। इस बात के ऊपर कोई आश्वासन देना बहुत कठिन बात होगी है । मैं माननीय सदस्य से यह कहना कि आज तक हमारे इच्छा का मंचाल है, इच्छा तो यही है कि जिनसे हमारे अधिकारी थे, जिन्होंने इमरजेंसी कमीशन के काम किया उनसे हम प्रच्छेद तरह से व्यवहार करें और सबके साथ समस्त का व्यवहार करें ।

दूसरे जो माननीय सदस्य न बाधु मेना द्वारा इमरजेंसी कमीशन के अधिकारियों को धापन देने की बात कहें, यह बात उन्होंने अपनी नोटिस में और दूसरी तरह में पहले बताया नहीं था, इसलिए अभी मेरे पास उसकी सूचना तो नहीं है, पर जब आपने इस बात की

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Minister will reply in the end after listening to all the points.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मुझे ज्यादा नहीं कहना है । यह सवाल जो 18 नवंबर को डा० भाई महावीर ने रखा था उसके उत्तर में यह बताया गया था कि 113 अफिसर ऐसे हैं जो रिटायर हुए थे 1969 की जून के पहले । श्रीमान्, जैसा कि डा० महावीर ने कहा, सवाल इस में यह है कि सब को इमरजेंसी कमीशन जो 1962 में बैठा उसने उन सभी को अफिसर बताया और यह जो उनको प्रकाश दिया गया यह जुलाई, 1967 में शुरू हुआ और 1970 में समाप्त हुआ । तो यह फेरबदल प्रोत्साहन था । कुछ को 1967 में रिटायर किया गया, कुछ को 1968 में किया गया, कुछ को 1969 में दिया गया और कुछ को 1970 में दिया गया । इसमें यह बात मैं मानता हूँ, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि शासन में इस तरह की बहुत सी दिक्कतें आती हैं । यह बात सही है कि अगर यह सुविधायें दे दी जायें तब जिनको रिटायर किया गया है उसमें ऐसा हो

उठाया है तो इसकी हम जरूर जांच करेंगे कि इसके बारे में क्या हो सकता है ।

डा० भाई महावीर : श्रीमान्,

श्री उपसभापति : मंत्री महाशय ने जो कहा उसके बाद भी आप त्वेरीफिकेशन चाहते हैं क्या ?

डा० भाई महावीर : Can I ask one small question ? मैं मंत्री जी से इतनी सी बात जानना चाहता हूँ कि दो वर्ष का जो समय है जिनके बीच में इसको इंटीग्रेशन किया गया और 8 जून, 1969 को आपने इस तरह का बनिफिट लागू किया तो क्या आपके पास प्राकड़े हैं कि अगर आप उस सारे बीच को एक साथ एक जैसा मजूक दें, एक ही व्यवहार उनके साथ करें तो कितने और लोग हैं जिनको यह बनिफिट मिलेगा और उससे सरकार के ऊपर कितना और आर्थिक बोझ पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ आश्वासन दिया भी है और कुछ नहीं भी दिया है । तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वे इतना तो कहें कि अगर वे उसे व्यवहारिक देखें तो उन दो साल के लोगों को भी इसमें शामिल कर लें ।

[श्री नथल गिडगार]

सकता है कि 113 से उनका नम्बर बढ़ जाय; क्योंकि घोर बोटिंगरी के लोग भी उसमें इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि डा० महावीर जी ने कहा अपरिपक्वी दिखाई पड़ता है कि डिस्ट्रिक्टमिनेशन हुआ है। उसको धारण भी अपने उत्तर में माना है। तो मैं यह चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने संकेत किया, मैं जानना चाहता हूँ कि घगर वे 1967 में रिटायर न किने जाते और सबको छुट्टी 1969 के बाद होती तो जो ज्यादा पुरान प्रच्युटी उनको सो-मबा सी रूपसे महीने के हिमाय से प्राप्त देने है धाज वह उन सबको देनी पड़ती। तो सिर्फ उन को गलती यह हुई कि वे दो साल पहले रिटायर हो गये। उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको गविस बाद के लोगों ने ज्यादा रही हो, लेकिन चूँकि 15 साल से कम थी, यही एक टेकनिकल प्वाइंट है। तो घगर सिर्फ कानूनी बात ही होगी तो उसको बात मैं नहीं कहता, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा धाज की परिस्थिति में स्थिति को देखते हुए और यह देखते हुए कि जिहोंने देश को अपना खून दिया है, जिन्होंने कुर्याती की है वह धाज बेकार पड़े हुए हैं इसे देख कर सचमुच में तकलीफ होती है। मंत्री जी ने कहा कि घगर इसका कोई हल निकल सकेगा तो वे देखेंगे। मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूँ कि घगर वे हल निकलना चाहेंगे तो जरूर हल निकल सकता है और नहीं चाहेंगे तो नहीं निकल सकता। घगर हल निकालने के लिए थ्योरो-क्रेटिक प्रपोज होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। टेकिनकल टिडीज में फस जायेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन घगर डिस्ट्रिक्टमिनेशन हों कि हम उनकी मदद करेंगे या जैसा डा० भाई महावीर जी ने कहा कि धाज भी जो प्लू का बानाकरण है उसमें हम को धफसरों और जवानों की धावश्यकता पढ़ सकती है और इसलिए घगर कायदे और कानून में वे धा सकते हैं तो उनको टैप किया जा सकता है। तो मैं एक बात और कह कर अपनी बात खत्म करूँगा। इस मामले को उपाध्यक्ष जो पिटीशनस कमेटी ने भी लिया था। 21 नवम्बर, 1968 को जो राज्य सभा की बैठक हुई थी, उसमें 20 धवकाश प्राप्त रिटायरेंट धाफिमस के हस्ताक्षरों से श्री मोहन धारिया जो ने एक पिटीशन दिया था जो पिटीशन कमेटी में लिया गया और काफी चिन्ता चिन्तियम के बाद उसमें धाखिर में क्या निर्णय हुआ था उसे पढ़ कर मैं खरम करूँगा। जो रिक्मेडेजन सर्वसम्मति में उन्होंने दी है, उसे पढ़ कर ही मैं खरम करूँगा। उस कमेटी में इस मामले को थोरोली

डिस्कस किया गया है और मैं यह भी बता दूँ कि धाज ने 43 परसेंट धादीमियों को परमानेंट भी किया जा सलेक्शन बोर्ड के नामने गये, लेकिन फिर भी 57 परसेंट वसे धोर उनके मामने ही टिकते हैं। उनके साथ इमरटी को बात की जाये, इमालिग मैं इस सवाल को उठा रहा हूँ और यह कमेटी को रिक्मेडेजन का पैरा 19 है।

19वा पैराधाफ है पैटीशन को कमेटी रिक्मेडेजन का :

"The Committee would like to point out that viewed in the context of the sense of frustration and disillusion which is looming large over a vast section of the educated unemployed in the country, the situation in respect of [the unemployed released Emergency Commissioned Officers portends further social tension. Government of India with its goal of Welfare State, which imposes on it the duty of looking after every citizen of

इसको मैं धामे नहीं पड़ता हूँ, मैं कवल यह दरख्वास्त करूँगा कि इन टिकतों के बावजूद भी इसका हल निकालियेगा ता निकल धायेगा, घगर इममन के साथ मजदूरी के साथ हल निकाला जायगा तब धाकई उनको इमदाद हो जायगी।

India, cannot afford to neglect the interest of this band of young and dedicated persons who had served the country at a very critical period of her history and in doing so had often been called upon for making the supreme sacrifice. The Committee would like to place on record their appreciation of the glorious service of these young-men to the Nation and feel that it is a national duty to settle them in gainful employment without delay."

SHRI VITHAL GADGIL (Maharashtra) : Sir, I will confine myself to the second point raised by Dr. Mahavir, namely, re-employment. Recently, about two months back, we live started a centre for jawans in Bombay, and believe me, within two months we received hundreds of applications for jobs from Emergency Commissioned Officers and Jawans. I am told that the principle of the Army organisation

is that the Army must be kept young. The result is that a man joins at the age of 18 particularly jawans—and comes out at the age of 30, and he gets a pension of Rs. 28/-. Therefore, I would suggest that in all Government services, particularly in the statutory corporations, certain percentage of vacancies should be reserved for Emergency Commissioned Officers and Jawans, and the Government should also try to persuade industrialists to have some vacancies. I would, therefore, request the Minister to give an assurance to this House.

SHRI A.G. KULKARNI (Maharashtra) : Persuasion does not work.

SHRI VITHAL GADGIL : . . . that he will try to take some such steps so that vacancies are reserved for them in Government, in statutory corporations and also in private industries.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : Sir, I also would like to join my voice with Mr. Gadgil on the question of re-employment of the HCOs.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : This is a very limited issue regarding discrimination.

SHRI CHITTA BASU : Please see the List of Business. It is on re-employment also; the notice says something like that.

SHRI VIDYA CHARANSHUKLA : That is not the question.

SHRI CHITTA BASU : It is like that in the List of Business.

Sir, the Petitions Committee had a very elaborate discussion on the problems of the ECOs—and both Mr. A. G. Kulkarni and I were on that Committee. Sir, without discussing much, I would merely implore upon the hon. State Minister of Defence that the entire Committee had taken the view that the ECOs had not been properly dealt with and it is necessary on the part of the Government to take better care of them. I would only like to mention a particular paragraph which will reveal 13 RSS/71—8.

the actual opinion or feeling or sentiments of the Committee in the matter of relief which has been provided for the ECOs. I read from page 8 of the Report :—

"The Committee would also like to record that comparatively greater opportunities have been offered to the released Emergency Commissioned Officers recruited in 1962-63 than what were offered to the officers released immediately after the 2nd World War."

Sir, again there are many things in this Report wherein the entire Petitions Committee headed by Mr. Chandra Shekhar had reviewed that we should have much more sympathetic consideration to the ECOs and, in that context, I would only want it to be let known to the House that the considerable number of persons who were recruited as ECOs was 9,083 and the number of those who were absorbed in permanent commissions was only 1,760. Rehabilitation so far has been given only to 1,586. Therefore, it means that about 5,000 ECOs have not been provided with any rehabilitation or re-employment. Another thing which is also very important to notice is that out of these 3,147 re-employed ECOs only 121 persons could find jobs in private organisations.

Therefore, Sir, there has not been an adequate opportunity for these ECOs to be re-employed after their retirement and yet when this Petitions Committee has taken a sympathetic view, I would urge upon the Government to reconsider the issue of their retirement and giving them the benefit of proportionate pension scheme. It has been reported to me that by terminal, the benefit that the Jawan gets, is a very small amount of Rs. 3,000 or Rs. 4,000 whereas had he been entitled to the proportionate pension scheme, he would have got something like Rs. 30,000 or so. This is a huge gap between the terminal benefit and the pension and the proportionate pension scheme. Therefore, having regard to these young men who bore the brunt of war in 1962 and 1965, they should have got a more sympathetic treat-

[Shri China Basu.]

ment from the Government of India. So far as the precedent is concerned, I do not know, I have got nothing, to say against any officer in any other Department, but these ECOs, in particular, are to be placed on a different footing. They ' bear the brunt of war and, therefore, their case has become all the more discriminatory. Only because of the fact that the ECOs joined earlier, have been denied this benefit. That is, those who retired before June 1969, they are being penalised although they have put in their services, they have undergone all the rigorous of life, they have built up the Commission. When the question of retirement comes, they have been deprived of these smaller benefits which they are entitled to and I think the Government should reconsider the issue and give a firm assurance to this House and having regard to the sympathetic view that has been taken by the Petitions Committee as a whole, he should reconsider the issue and give them the benefit of proportionate pension scheme.

SHRI KRISHAN KANT (Haryana) : Mr. Deputy Chairman, I speak more with agony and pain rather than anger. When our jawans and military people are guarding our borders, a sensitive Minister like Mr. Shukla came to this House without any decision.

SHRI A.G. KULKARNI : Emotional or sensitive ?

SHRI KRISHAN KANT : He is very sensitive to the difficulties and pains of the people. I hope Mr. Kulkarni understands me.

When the records of this discussion go to the press today or tomorrow, what will the people feel ? The whole fault of the people, who have not been given pension benefit is that they responded to the call of patriotism first. It was the intensity of patriotism because of which they are suffering and how are we dealing with that question ? Maxim Gorky, while writing one of his novels, said that those people who

continue to eat copper, their souls get stunted. Like that, Dhanna said while dealing with money matters that the wooden bureaucrats always think of money in plus and minus and never in terms of the human beings. The citizens of the country would be suffering if these jawans did not protect our frontiers. I do not know why before coming to this House the Ministry of Defence did not get clearance from the Ministry of Finance and come with the declaration : "Yes here is a misjate¹-on our part and we are rectiVug this." Here I will give afl example of what Gandhiji said in 1939 or 1940. All of a sudden, one day in 'Harijan' he wrote : "I am increasing the daily allowance of the spinners from two annas to eight annas." People asked Gandhiji, "There was no need about it. there was no petition or agitation by spinners." But there was no need of putting petitions before Gandhiji because his fingers were on the pulse of the people, he new the difficulties of the people, he knew the tortures. That is why all of a sudden without any protest, he increased the dail> allowance of spinners. That is the picture of a real democratic man, and that should be of a democratic country and the democratic Government must behave with the people in this manner. And on this issue I think the Petitions Committee is there. I do not want to quote but my friends have quoted. It seems that the Government is deaf, the bureaucracy is deaf and nothing gets moved even at this lime when we are faced with another danger. What will our jawans think ? They will feel, if we lay down our lives tomorrow for the sake of oui country will our families be looked after ? Mr. Deputy Chairman, I would appeal to the Government to say something today that within a period of one week or so this mistake will be rectified after due consultation with the Finance Ministry. Let not the Finance Ministry behave like Dhanna Seth in this respect. They should be responsive and within one week this should be rectified in fairness to those who have served this country and who have been thrown out because of a certain policy of the Government. Otherwise they could

have remained in the Army. The Government's own policy mistake should be rectified. Thank you.

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभापति जी, माननीय सदस्य श्री महावीर जी ने प्रश्न पूछा था कि इसमें कितने आफिसर हैं, जिनको यह तारीख के खयाल के कारण उन सुविधाओं से बंचित रहना पड़ा। ऐसे आफिसरों की संख्या जो तीनों मविसेज को बिलांग करते हैं, जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के हैं उनकी संख्या 113 है, इस तरह से 113 हमारे अधिकारी हैं, इसमें कितना हमारा खर्चा घटता और बढ़ता है, इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। पर जहां तक मैं समझता हूँ इस प्रश्न में ऐसे का सवाल नहीं है, बल्कि जितना सवाल नियम का है और उसके व्यापक प्रभाव में उसके ऊपर इस तरह का निर्णय किया गया है।

मैं माननीय सदस्य श्री कृष्णकोट्टा का अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने इस वक्त जोरों से इस केस का और इस विषय का समर्थन किया और कहा कि इसके ऊपर तत्काल निर्णय होना चाहिये। मैंने पहिले ही कहा कि हम इस प्रश्न पर फिर से विचार करेंगे और इस बात को देख कर कि किस तरह से हम इसको एक सीमित प्रश्न मान कर उसके ऊपर कुछ निर्णय ले सकते हैं। यदि इसकी व्यापकता को कम कर सकते हैं तो एक सीमित प्रश्न मान कर उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं, ताकि उसकी व्यापकता पर प्रभाव न पड़े और तब मैं समझता हूँ कि उस पर निर्णय लेने में कितनी सुविधा होगी।

SHRI AK.BAR ALIKHAN
(Andhra Pradesh) : This must be treated differently.

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो सर्वसम्मति से अपने विचार और दृष्टिकोण प्रकट किये, उससे भी हम लोगों को इस पर विचार करने के लिए काफी साबधा मिलेगी और उसके बारे में ठीक निर्णय करने हमें सहायता मिलेगी।

श्री नवल किशोर जी ने कहा कि मन होगा तो निर्णय हो सकते हैं। मन तो है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मन होने पर भी निर्णय हो सकेगा या नहीं। (Interruption) आपकी जो आशा है वह पूरी होगी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता हूँ।

श्री गार्डगिल और श्री चित्त बामु ने कुछ दूसरे प्रश्न उठाये और कहा कि जो हमारे कमिश्नड आफिसर हैं, उन्हें सेना से निकालने के बाद कोई काम नहीं मिला

है। यह बात ठीक है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग बाकी हैं, जिनको अभी तक काम नहीं मिला है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि सरकार के द्वारा हर तरह के प्रयत्न किये जा रहे हैं, ताकि उन्हें तरह-तरह का काम दिया जा सके। जो सधीय लोक सेवा आयोग है, उसकी परीक्षा में उनके स्थान सुरक्षित है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी सरकार के अन्तर्गत संस्थान हैं और सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए विशेष रूप से प्रवधान किया गया है। इसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे इंडियन आयाल कारपोरेशन है, उसमें जिस तरह से अन-एम्प्लाइड इंजीनियर्स को पेट्रोल की एंजेंसी देने के लिए कहा गया है, उसी तरह की सुविधा इन लोगों को भी दी जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि नौकरियों में और दूसरे धंधों में इन लोगों को सुविधा दी जाय, जिससे यह लोग काम कर सकें। इसका फायदा बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बच गये हैं, जिनकी समस्या का हल नहीं निकल पाया है और वे बेकार हैं। हमारे प्रयत्न जारी हैं कि इस समस्या का भी हल निकालें; क्योंकि यह बात ठीक है कि जो व्यक्ति हमारे देश की संकट की घड़ी में अपने प्राणों की बाजी लगा कर नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और कठिनाई का, संकट का समय बीत जाने के बाद हम उनके साथ साधारण रूप से व्यवहार करें, उनकी मांगों पर साधारण ढंग से सोच विचार करें तो फिर हमारे देश के जवानों के मनोबल में कमी होना या देश के शासन के प्रति उनके मन में अविश्वास होना अस्वाभाविक बात नहीं होगी।

DR. BHAI MAHAVIR : Will you try and reabsorb them in the Army

श्री विद्या चरण शुक्ल : आर्मी के लिए जो सुझाव है, इससे मैं नहीं समझता कि हम लोग कुछ कर सकते हैं; क्योंकि जब यह सेना वाले जवानों को लेते हैं तो उनकी उम्र के बारे में शारीरिक स्थिति के बारे में और बहुत सी जो दूसरी उपलब्धियां रहती हैं, उनके बारे में सोच विचार करके लेते हैं। यदि उसके अन्तर्गत वे आते तो मैं नहीं समझना दुबारा लिए जाने में किसी तरह की आपत्ति होगी, परन्तु जो एक स्टैंडर्ड नियम किया गया है, उसके अन्तर्गत नहीं आये तो मैं नहीं समझता कि यह देश के हित में होगा कि उन स्टैंडर्ड को नीचा करके या डीला करके उनको लेने का यत्न करें। जो दूसरी बहुत सी आर्थिक गतिविधियां हमारे देश में चल

[श्री विद्या चरण शर्मा]

रही हैं, उनमें हम लोगों को सहायता करनी चाहिए कि उनको सम्मिलित कर सकें। मैं पुनः माननीय सदस्यों को विशेष कर डा० महावीर और श्री कृष्ण-कान्त जी और दूसरे भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया और इस प्रश्न की ओर शासन का और देश का ध्यान आकर्षित कराया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The *House* stands adjourned 'ill M A. M. on Monday, the 29th November.

The House then adjourned at forty-three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 29th November, 1971.